on 1.10.1991 was of the order of 15.6 million tonnes, which is considered to be sufficient to meet the reasonable requirements of the Public Distribution System.

Assistance to draught affected areas in Madhya Pradesh

1500. SHRI AJIT P. K. JOGI:
SHRI B. K. HARIPRASAD:

Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) what are the names of the States and areas of the country where crop yield has declined sharply due to lack of rain this year; and

(b) what assistance Government have provided to the State Government for providing employment to the migrating workers there especially Mahakaushal, Chhatisgarh and Vindhyachal areas of Madhya Pradesh?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI MULLAPPALLY RAMACHANDRAN): (a) It is too early to indicate the size of the crop yield based on the crop cutting experiments for the current year, as the same have not yet become due from the States. However, as per the current assessment, the crop yields of some crops are expected to be less this year, as compared to previous year, in the States of Uttar Pradesh, Bihar Haryana, Rajasthan, Madhya Pradesh, Maharashtra, Gujarat, etc. on account of dry spelle and aberrant weather conditions in these areas.

(b) Under the existing scheme of financing relief expenditure, the State Govt. is required to incur all expenditure from the corpus of the Calamity Relief Fund (CRF) allotted to the State. A State level Committee headed by the Chif Secreatary is competent to decide on all matters including the norms of assistance. Madhya Pradesh has an annual Calamity Relief Fund of Rs. 37.00 crores consisting of Rs. 27.75 crores Central contribution and Rs. 9.25 crores State's contribution. During 1991-92, Central Govt. has already released three quarterly instalments of its share amounting to Rs. 20.81 crores.

बीजों का उत्पादन और वितरण

1501. **श्री राम जेठमलानी :**
सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में उन्नत किस्म के बीजों के उत्पादन तथा विपणन के लिए 1963 में राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना की गई थी ;

(ख) क्या यह सच है कि निगम अपने उद्देश्य में विफल रहा है ;

(ग) यदि हां, तो इस निगम द्वारा 1990-91 के दौरान विभिन्न किस्मों के बीजों की कुल कितनी-कितनी मात्रा का उत्पादन तथा वितरण किया गया और इस निगम द्वारा देश में बीजों की कुल आवश्यकता के कितने प्रतिशत भाग को पूरा किया जा सका ;

(घ) क्या यह भी सच है कि पिछले वर्ष देश में बीजों का आयात करना पड़ा था ; यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) निगम के कार्यकरण के संबंध में सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार कर रही है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचंद्रन) : (क) जी, हां ।

(ख) राष्ट्रीय बीज निगम ने कम्पनी के संगम के ज्ञापन के तहत यथा परिभाषित अपना कार्य किया है ।

(ग) राष्ट्रीय बीज निगम ने वर्ष 1990-91 के दौरान लगभग 1.96 लाख क्विंटल प्रमाणित बीज का उत्पादन किया। फसल तथा किस्म वार ब्यौरा अनुपत्र में दिया गया है इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय बीज निगम ने 11.000 क्विंटल आधारी बीज तथा 1753 क्विंटल प्रजनक बीज का भी उत्पादन किया। राष्ट्रीय बीज निगम ने उसी अवधि के दौरान 407 लाख क्विंटल प्रमाणित बीज का वितरण किया। ब्यौरा अनुपत्र पर दिया गया है (देखिए परिशिष्ट 161, अनुपत्र संख्या 44) देश की प्रमाणित बीज की कुल आवश्यकता में राष्ट्रीय बीज निगम का अंश लगभग 3.25% है।

(घ) 1990-91 के दौरान बीजों तथा पौध रोपण सामग्रियों के आयात इस प्रकार है:—

बीज	मात्रा
सब्जी	85397.356 किलोग्राम और 300 सं०
पुष्प	74.295 किलोग्राम
तिलहन	5416.00 किलोग्राम 130000 सं०
दलहन	633.90 किलोग्राम
मोटे अनाज	698.56 किलोग्राम
कुल :	92220.111 कि० ग्रा० 133000 सं०

(ङ) राष्ट्रीय बीज निगम के कार्यों को उपचारात्मक रिपोर्ट तैयार करने के लिए विश्व बैंक सहायता प्राप्त राष्ट्रीय बीज परियोजना के तहत भारत सरकार द्वारा सलाहकार नियुक्त किए गए हैं।

किसानों की दुर्दशा के संबंध में श्वेतपत्र

1102. **श्री सत्य प्रकाश मालवीय:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार किसानों की दुर्दशा पर एक श्वेतपत्र जारी करने का विचार रखती है; और

(ख) यदि हां, तो किसानों की दशा में सुधार करने के लिए सरकार ने क्या-क्या योजनाएं तैयार की हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचंद्रन): (क) और (ख) ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है। तथापि, किसानों की बेहतर स्थिति सुनिश्चित करने के लिए केन्द्रीय सरकार ने कई उपाय शुरू किए हैं। इनमें प्रमुख कृषि जिन्सों के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करना, निर्यात अधिशेषों के सृजन के लिए नीति तैयार करना, उचित दामों पर अनिवार्य आदानों की उपलब्धता सुनिश्चित करना, ऋण और विपणन संबंधी अवसंरचना पर्याप्त मात्रा में मुहैया कराना, आदि शामिल है।

Loss of Paddy production in Andhra Pradesh

1503. DR. YELAMANCHILI SIVAJI: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) what has been the loss of paddy production due to Tungru virus in Andhra Pradesh during the last five years, year-wise; and

(b) what steps Government have taken in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI MULLAPPALLY RAMACHANDRAN): (a) Sir, as reported by the State Government of Andhra Pradesh Rice Tungru Virus (RTV) disease in Andhra Pradesh was recorded only during Kharif 1990 and Kharif 1991 with estimated production losses of 3.42 lakh tonnes and 0.05 lakh tonnes respectively.

(b) The following steps have been taken by the Government to contain the disease:

(i) Soon after noticing the disease during Kharif 1990 proper control measures were adopted covering